अशोका एक्सप्रेस

SMA - Ashoka Express Publication

Member : CNSI, Delhi निर्वाण प्राप्त गीता भारती राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

Website :-www.ashokaexpress.com YouTube ashokaexpress

E-mail :-ashoka.express@live.com ashokaexpress

संपादक :- विजय कुमार भारती
प्रबंधक :- सज्जन सिंह

• वर्ष: 29 • अंक : 19 • नई दिल्ली • 23 से 31 मई 2026 • पृष्ठ : 8 • मूल्य : 2 रूपये

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत से इनकार करने के फैसले को बड़ी बेंच में भेजा

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर की मांग- शिक्षामंत्री इस्तीफा दें

अभिजीत के माता-पिता बोले- 2 रातों से नहीं सोए, डर है बेटा गिरफ्तार न हो जाए

नई दिल्ली । कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके शुक्रवार को सोशल मीडिया पेज बनाने के 7 दिन बाद पहली ऑनलाइन पिटीशन लेकर लाए। जिसमें उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षामंत्री के इस्तीफे की मांग की है। दीपके ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा- आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं। जिसमें शिक्षामंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आप सब लोग यादा से यादा इस पिटीशन पर साइन कीजिए। ताकि सिस्टम की गलती पर सवाल उठ सके। अभिजीत ने 'कॉकरोच जनता पार्टी'सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी के विरोध में बनाई है। सीजेआई ने 15 मई को सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगारों को 'कॉकरोच' कहा था।

पेरेंट्स नहीं चाहते बेटा राजनीति में जाए

उधर कॉकरोच जनता पार्टी पेज के

इंस्टाग्राम पर अचानक लोकप्रिय होने से उसके फाउंडर अभिजीत दीपके के माता-पिता बहुत यादा परेशान हो गए हैं। उन्हें डर है कि उनका बेटा किसी मुसीबत में पड़ सकता है। उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अभिजीत के पेरेंट्स भगवान और अनीता दीपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रहते हैं। दोनों ने गुरुवार को एक मराठी न्यूज चैनल को बताया- हम अपने बेटे को राजनीति में नहीं भेजना चाहते थे। अभिजीत के इस कदम के बारे में सुनकर हमारी रातों की नींद उड़ गई है। भगवान ने कहा- आज का माहौल देखकर डर लगना स्वाभाविक है। चाहे उसके कितने भी फॉलोअर्स क्यों न हों। उसने खुद भी भारत लौटने पर गिफ्तार होने का डर जाहिर किया है। वह मशहूर हो गया है, और ऐसे लोगों को अक्सर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पिछली दो रातों से मैं इसी चिंता में सो नहीं पाया हूं कि उसके साथ क्या हो सकता है। अभिजीत की मां ने कहा- हमें कॉकरोच पार्टी के बारे में अपने एक पड़ोसी से पता चला था। मैं चाहती हूं बेटा राजनीति से दूर रहे। वह आप के साथ काम कर चुका था। उस समय भी मैंने उससे कहा था कि हमारा राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है और उसे कोई नौकरी कर लेनी चाहिए।

नीट छात्रा से दरिंदगी- अजय राय बोले- न्याय के लिए घेरेंगे सीएम आवास, पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी से गरमाई सियासत

महोबा । महोबा जिले में अपहरण व दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली नीट की तैयारी कर रही छात्रा से मिलने शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय महोबा पहुंचे। उन्होंने पीड़िता से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीड़िता को वह न्याय दिलाकर रहेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें मुख्यमंत्री का घर घेरना पड़े। उन्होंने पीड़िता को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। मध्यप्रदेश के जनपद छतरपुर के एक गांव निवासी 25 वर्षीय युवती महोबा में किराये का कमरा लेकर नीट की तैयारी कर रही थी। 30 अप्रैल को वह लाईब्रेरी से घर लौटते समय लापता हो गई थी। 16 दिन बाद युवती को पुलिस ने बरामद किया था। बरामद होने के बाद युवती ने आरोपियों पर अपहरण, दुष्कर्म व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। पीड़िता का आरोप था कि आरोपियों ने उसे बंधक बनाए रखा। साथ ही, नशीले इंजेक्शन दिए और सिगरेट से भी दागा। इस मामले में पुलिस ने धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए तीन

आरोपियों को जेल भेजा है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की गई हैं। युवती के बयान देने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इसमें युवती दुष्कर्म का आरोप लगाने वाले युवक से शादी करती नजर आ रही है। इसमें स्वेच्छा से विवाह किए जाने जैसे तथ्य दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अपहृता व आरोपी युवक के हाईकोर्ट में संयुक्त याचिका डाले जाने, स्वेच्छा से विवाह किए जाने और परिजनों से सुरक्षा दिए जाने की पुलिस बात कह रही है। शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय महोबा पहुंचे और नीट की तैयारी कर रही छात्रा से पूरी घटना की जानकारी ली। प्रदेश अध्यक्ष ने इस घटना को शर्मनाक बताया। कहा कि छात्रा के साथ अपराधियों ने 16 दिन तक शोषण किया। नशे के इंजेक्शन लगाए। तीन मई को छात्रा का नीट का पेपर था। 30 अप्रैल को छात्रा का अपहरण कर लिया गया। वहीं, अपराधी छात्रा से जबरन शादी भी करते हैं और उसे खुद लाकर घर छोड़ते हैं। आरोप लगाया कि छात्रा को पुलिस नहीं लाई। पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। कहा कि उन्हें महोबा आने से रोकने के लिए कई स्थानों पर पुलिस लगाई गई, लेकिन वह पीड़िता से मिलने पहुंचे। कांग्रेस हर जगह जाएगी। दुष्कर्म पीड़िता नीट छात्रा से मिलने महोबा आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान से सियासत एक बार फिर गरमा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वह पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद लौटते समय कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहते सुनाई दे रहे हैं। इसके बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश नजर आ रहा है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली -एक जाल, जिससे मुक्ति आवश्यक

हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था एक ऐसा जाल बन गई है, जिसमें लाखों-करोड़ों युवा फंस रहे हैं। यह प्रणाली न तो सच्चे कौशल विकसित करती है और न ही नवाचार को प्रोत्साहित, बल्कि यह छात्रों को एक सांचे में ढालकर औसत जीवन की ओर धकेल रही है। बदलाव की मांग अब न केवल जरूरी, बल्कि अनिवार्य बन चुकी है। सफल उद्यमियों की कहानियां गवाह हैं कि बड़ी कंपनियों के संस्थापकों ने अक्सर पारंपरिक शिक्षा के इस जाल से खुद को बचाया। उनकी सफलता का राज रट्टा मारने या परीक्षा में अंक लाने में नहीं, बल्कि व्यावहारिक सोच, जोखिम लेने की क्षमता और निरंतर सीखने में छिपा है। जहां अमीर बच्चे बेहतर संसाधनों और अतिरिक्त कोचिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, जबकि गरीब परिवार के बच्चे सीमित अवसरों में संघर्ष करते रह जाते हैं। शिक्षा की इस व्यवस्था में रचनात्मकता को कुचला जा रहा है। उदाहरण के लिए, अधिकतर कक्षाओं में बच्चों को सरल दृश्य बनाने या मानकीकृत उत्तर लिखने को कहा जाता है, न कि स्वतंत्र सोच विकसित करने को। परिणामस्वरूप, वे किसी बड़े कारखाने की असैंबली लाइन से निकलने वाले उत्पादों की तरह एक जैसे बन जाते हैं। समाज और परिवार प्रतिशत और रैंकिंग की दौड़ में बच्चों को धकेल रहे हैं। ऐसे में जीवन को 'दौड़' बताकर तनाव बढ़ाया जा रहा है, जबकि वास्तव में हर बच्चे की अपनी गति और प्रतिभा होती है, जिस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। कुछ अपवादों को छोड़ कर कक्षाएं अभी भी सौ साल पुरानी शैली में चल रही हैं। बोर्ड, चॉक और रट्टा-आधारित पढ़ाई छात्रों को भविष्य के लिए तैयार नहीं कर पा रही। अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रसिद्ध उदाहरण यहां पूरी तरह लागू होता है, मछली को पेड़ पर चढ़ने की परीक्षा देकर उसकी बुद्धिमत्ता का आकलन करना अन्याय है। उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था की जड़ें ब्रिटिश काल से जुड़ी हैं, जब 1835 में एक नीति बनाई गई, जिसका उद्देश्य सच्चा सशक्तिकरण नहीं बल्कि आज्ञाकारी नागरिक तैयार करना था। आज भी स्कूल-कॉलेज उन पूर्वनिर्धारित भूमिकाओं के लिए ग्रैजुएट तैयार कर रहे हैं, न कि नवप्रवर्तक या नेता। ग्रेड्स्डग सिस्टम बुद्धिमत्ता को केवल परीक्षा अंकों तक सीमित कर देता है, जबकि संचार, समझौता कौशल और समस्या-समाधान जैसे जीवन-महत्वपूर्ण गुणों की उपेक्षा की जाती है। ऐसे में इन सब के परिणाम भयावह हैं। स्नातकों में से आधे से अधिक नौकरी के योग्य नहीं पाए जाते। कॉर्पोरेट जगत में प्रवेश के बाद संचार की कमी, सकारात्मक दृष्टिकोण की कमी और निरंतर सीखने की इच्छा की कमी उजागर हो जाती है।

जर्मनी जैसे देशों में दोहरी शिक्षा प्रणाली है, जहां सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव जुड़ा होता है। लेकिन हमारे यहां छात्र स्नातक होने तक केवल किताबी ज्ञान पर ही निर्भर रहते हैं। नतीजा-अच्छे अंक लाने वाले छात्र भी बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। आपको याद होगा जब 2025 में राजस्थान के चपरासी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 53,000 पदों की भर्ती के लिए करीब 25 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। इनमें से लगभग 85 से 90 प्रतिशत उम्मीदवार उच्च शिक्षित (ग्रैजुएट, पोस्ट-ग्रैजुएट, बी.टैक और पीएच.डी.) थे। इस जाल का सबसे दर्दनाक पहलू मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव है। नौकरी न मिलने की निराशा से हर साल हजारों छात्र आत्महत्या कर लेते हैं या गुनाह का रास्ता अपना लेते हैं। आई.आई.टी. जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में दाखिला पाने की होड़ में व्यक्तिगत रुचि और क्षमता को नजरअंदाज किया जाता है, जिससे हताशा बढ़ती है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा डिग्री-केंद्रित हो गई है, कौशल-केंद्रित नहीं। इसलिए समय आ गया है कि हम डिग्री से कौशल की ओर मुड़ें। वित्तीय शिक्षा अनिवार्य हो।

बच्चों को एसेट-लायबिलिटी का अंतर, मुद्रास्फीति से लड़ना, निवेश बनाम खर्च और जल्दी बचत करने का महत्व सिखाया जाए। स्कूलों में कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटैलिजैंस, डिजिटल मार्कीटिंग और आर्थिक मामलों जैसे भविष्योन्मुखी विषयों को भी शामिल किया जाए। इसके साथ ही बिजनैस सिमुलेशन प्रोजैक्ट्स शुरू किए जाएं, ताकि बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरियां पैदा करने वाले बनें। जोखिम लेने की क्षमता विकसित करने के लिए गणना-आधारित प्रयोगों को प्रोत्साहन मिले। हमारे शिक्षक इस व्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए उनका नियमित प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणों से लैस होना और प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन जरूरी है। आज के भाग-दौड़ भरे युग में मानसिक स्वास्थ्य और जीवन कौशल भी शिक्षा का हिस्सा बनें।

बच्चे गणित तो सीखते हैं लेकिन तनाव प्रबंधन नहीं। समय प्रबंधन, नागरिकता भावना, संचार कौशल 7वीं कक्षा से अनिवार्य हों। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच विकसित करना होना चाहिए। सरकार, शिक्षाविद्, अभिभावक और समाज को मिलकर काम करना होगा। तभी हमारा युवा वर्ग न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि राष्ट्र-निर्माण में योगदान देगा।

सम्पादकीय

रूबियो की भारत यात्रा

राष्ट्रपति ट्रम्प के अमेरिका का पुनः सरपरस्त बनने के बाद भारत के साथ इस देश के सम्बन्धों का मंथन जिस प्रकार चल रहा है उसके विश्व व्यापी आयाम हैं क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र होने के साथ ही दुनिया की तेज गति से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्था का देश भी है। दोनों देशों के सम्बन्ध भारत के स्वतन्त्र होने के बाद से हिचकोले भी खाते रहे हैं मगर 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद इनमें गुणात्मक परिवर्तन आया और अमेरिका ने भारत को बाजार मूलक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान भी अपने पूंजी निवेश से दिया परन्तु भारत में 1991 के बाद बनी सरकारों ने इस मोर्चे पर एहतियात से काम लिया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए उसी हद तक खोला जिससे उसके राष्ट्रीय आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव न पड़ सके। 1991 के बाद के भारत-अमेरिकी सम्बन्धों की यदि समीक्षा की जाये तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज की तारीख में भारत अमेरिका को अधिकतम निर्यात करने वाला देश है और व्यापार सन्तुलन इसके पक्ष में करीब 46 अरब डॉलर का है। यह स्थिति तब है जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है और आधुनिकतम टैक्नोलॉजी का अधिष्ठाता भी समझा जाता है। अतः भारत को इसके साथ अपने सम्बन्ध निर्धारित करते समय सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करना होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा 'महाजन' देश भी है जिसके चलते यह आपसी सम्बन्धों में सबसे पहले अपने हितों को साधता है। भारत के साथ इसके सम्बन्धों की भी हमें निरपेक्ष भाव से इसी दृष्टि से समीक्षा करनी होगी और सोचना होगा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने पिछले दिनों भारतीय आयात माल पर सर्वाधिक ऊंची 50 प्रतिशत शुल्क दरें क्यों लागू की थीं ? हालांकि इसके बाद अमेरिका की ओर से भारत के साथ जिस व्यापार समझौते की घोषणा की गई और भारत ने भी जिसे स्वीकार किया, उसमें शुल्क दरों में बदलाव किया गया परन्तु यह मानना पड़ेगा कि इस समझौते में भारत ने अपने कृषि क्षेत्र के लिए सीमित समझौतावादी नीति को भी अपनाया जिससे भारतीय राष्ट्रीय आर्थिक हित सधे रहे और भारत का इसके साथ व्यापार सन्तुलन लाभ में ही चलता रहे। हालांकि इस समझौते की भारत के राजनीतिक क्षेत्रों में तीखी आलोचना हुई परन्तु अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रम्प की शुल्क नीति के विरुद्ध फैसला आने के बाद यह समझौता बट्टे-खाते में चला गया है और दोनों देश नये सिरे से कारोबारी करार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका के विदेश मन्त्री श्री मार्को रूबियो इसी पृष्ठभूमि में आगामी 23 मई से भारत की चार दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं जिसे भारत के नजरिये से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी दौरान नई दिल्ली में 'क्वाड' संगठन देशों के विदेश मन्त्रियों की बैठक भी होगी जिसमें श्री रूबियो हिस्सा लेंगे। ट्रम्प के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद किसी अमेरिकी विदेश मन्त्री की यह पहली भारत यात्रा होगी। अपनी इस यात्रा में श्री रूबियो भारत के साथ व्यापार के अलावा ऊर्जा व रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भी बातचीत करेंगे। दरअसल अगले महीने फ्रांस में दुनिया के सात अग्रणी देशों का जी-7 का शिखर सम्मेलन हो रहा है जिसमें प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी को भी न्यौता दिया गया है।

VB- G RAM G : ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम पर दोहरा हमला

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) संभवत- स्वतंत्रता के बाद बनाया गया सबसे कारसाज कानून था। यह कानून सिर्फ गरीबों के पक्ष को कोई हस्तांतरण ही नहीं करता था। यह कानून रोजगार निर्माण की महज एक योजना स्थापित नहीं करता था, जैसी इससे पहले आए ''काम के लिए अनाज'' कार्यक्रमों ने की थी। यह कानून, चाहे सीमित रूप से ही सही, रोजगार के अधिकार को मान्यता देता था। मनरेगा कानून इसका प्रावधान करता था कि हर परिवार से एक व्यक्ति को मांगने पर, 100 दिन तक का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तदानुसार इस कार्यक्रम ने दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार निर्माण कार्यक्रम स्थापित किया था। यह एक ऐसा कार्यक्रम था जो अभाव के मारे ग्रामीण परिवारों को उल्लेखनीय राहत मुहैया कराता था। हालांकि, इस अधिकार को संवैधानिक मान्यता हासिल नहीं थी, फिर भी मनरेगा को स्थापित करने वाला कानून संसद द्वारा काफी बहस तथा चर्चा के बाद पारित किया गया था। और यह चर्चा सिर्फ संसद तक ही सीमित नहीं थी बल्कि सांसदों तथा व्यापक रूप से समाज के बीच भी हुई थी, जिसमें अकादमिक अर्थशास्त्री, सार्वजनिक बुद्धिजीवी, मजदूरों के प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी संगठन, सभी की हिस्सेदारी थी। और यह कानून सर्वसम्मति से पारित हुआ था, जो इसे अर्द्ध-संवैधानिक वचन का दर्जा दे देता था। बेशक, उस समय यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलाइंस (यूपीए) सरकार के अंदर भी इस पर असहमति के स्वर भी थे, फिर भी बाहर से इस सरकार को समर्थन दे रहे वामपंथ के दबाव की आखिरकार जीत हुई थी और सभी पार्टियां इसका समर्थन करने के लिए तैयार हो गयी थीं, जिनमें भाजपा भी शामिल थी।

वर्गीय है भाजपा की मनरेगा के प्रति दुश्मनी

इस कानून के जरिए शुरू हुई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ने सिर्फ ग्रामीण गरीबों के लिए ही जीवन रेखा मुहैया नहीं करायी थी बल्कि शहरी गरीबों को भी जीवन रेखा मुहैया करायी थी, जैसा कि कोविड की महामारी के दौरान साफतौर पर देखने में आया था, जब बड़ी संख्या में शहरी गरीब अपने गांवों को लौटने के लिए मजबूर हो गए थे और वहां इस योजना के अंतर्गत मिल रहे काम ने ही उनकी मदद की थी। चाहे बहुत सीमित हद तक ही सही, इस कानून ने समाज में वर्गीय ताकतों के संतुलन एक तब्दीली की थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि इसकी वजह से मजदूरी के बढ़ने का दबाव बनने की संभावना से भूस्वामी धनिक खतरा महसूस करते थे। बात गरीब मजदूरों पर सामाजिक नियंत्रण छूट जाने की भी थी, इस डर की भी थी कि गरीब अब कहीं हाथ से बाहर ही नहीं निकल जाएं। मनरेगा के प्रति यह वर्गीय विरोध, भाजपा के गिर्द संघनित हो गया, जो तब तक सत्ता में आ चुकी थी और जिसने इसके लिए काफी भरोसा अर्जित कर लिया था वह अपने इस वर्गीय पूर्वाग्रह को उजागर करती है तब भी, इस पूर्वाग्रह को जैसा कि उसका कायदा ही है, ''विकास'' की चिंता के आवरण में छुपा सकती है। अब यह दलील दी जाने लगी कि जिन अमूल्य संसाधनों का उपयोग ''विकास'' के लिए किया जा सकता था, उन्हें इस योजना के अंतर्गत, जो कि भ्रष्टाचार से ग्रसित है, बर्बाद किया जा रहा था। भाजपा के मामले में, वर्गीय पूर्वाग्रह के चलते मनरेगा का जो उसका विरोध था, उसे यह तथ्य और पुख्ता कर रहा था कि भाजपा जैसे फासीवादी संगठन अपरिहार्य रूप से जनता को कोई अधिकार दिये जाने के खिलाफ होते हैं। उनका जोर जनता के कर्तव्यों पर होता है न कि अधिकारों पर।

नये कानून की आड़ में हमला

इसी सब का नतीजा था कि मनरेगा की जगह एक नया कानून बनाया गया है। इस कानून का बनाया जाना भी एक तरह से हाथ की सफाई का मामला था। यह कानून जल्दबाजी में संसद में पेश किया गया, इस पर मुश्किल से ही संसद में कोई बहस हो पायी और उसे फटाफट ध्वनि मत से पारित करा दिया गया। और अब 1 जुलाई से यह कानून लागू भी हो जाएगा। इन नये कानून के जरिए, पहले वाले कानून से अनेक बदलाव किए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि जहां पहले वाली योजना के तहत खर्चा 90:10 के अनुपात में केंद्र तथा रायों को वहन करना होता था, अब यह खर्चा केंद्र और रायों द्वारा 60:40 के अनुपात में उठाया जाएगा ('विशेष श्रेणी के राय' ही इसका अपवाद होंगे)। इस बदलाव का फैसला केंद्र सरकार ने इकतरफा तरीके से कर लिया है, जिस संबंध में राय सरकारों से कोई परामर्श ही नहीं किया गया है। अब वर्तमान नव-उदारवादी निजाम में राय सरकारें पहले ही वित्तीय संसाधनों की तंगी से जूझ रही हैं। इसका एक बड़ा कारण गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) है, जिसने उस बिक्री कर की जगह ले ली है, जो इससे पहले तक राय सरकारें अपने विवेक के हिसाब से लगा सकती थीं। ऐसे हालात में रायों को इस योजना का 40 फीसद बोझ उठाने के लिए मजबूर करने का एक ही अर्थ है कि इस योजना का गला फंड की तंगी से घोंटा जा रहा होगा और इसका दोष रायों के सिर पर मढ़ा जा रहा होगा। नये कानून से ऐसा भी लग रहा था कि मनरेगा के सार्वभौम कवरेज का त्याग किया जा रहा है और इसकी मांग-संचालित प्रकृति का भी त्याग किया जा रहा है, जो इसे रोजगार का अधिकार देने के जैसा बनाती थी। इसकी वजह यह है कि नयी योजना सिर्फ अधिसूचित ग्रामीण इलाकों में ही लागू होनी थी (हालांकि इन इलाकों में रोजगार के अधिकतम दिन, पहले की योजना के 100 से बढ़ाकर 125 किए जाने वाले थे)। बहरहाल, केंद्र सरकार के प्रवक्ताओं ने इससे इंकार किया है। नये कानून के पारित होने के फौरन बाद उन्होंने दावा किया था कि मनरेगा की तरह सार्वभौम कवरेज बना रहेगा और योजना की मांग संचालित प्रकृति भी अक्षुण्ण रहेगी, जबकि काम के दिनों की संख्या पहले के 100 दिन से बढ़ाकर 125 कर दी जाएगी।

पहले ही समेटा जा रहा है रोज़गार

लेकिन, यह नया कानून क्या प्रावधान करता है और क्या प्रावधान नहीं करता है, यह इसे देखते हुए अप्रासांगिक ही हो जाता है कि पुरानी योजना को अब किस तरह से संचालित किया जा रहा है और यह इस योजना को समेटे जाने के सिवा और कुछ नहीं है। यह इस योजना के संबंध में 2025-26 पर आयी रिपोर्ट से स्वत-स्पष्ट है। यह रिपोर्ट लिबटैक इंडिया द्वारा तैयार की गयी है, जो कि अकादमिकों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक कंसोर्शियम है। यह रिपोर्ट बताती है कि मनरेगा के अंतर्गत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 2024-25 की तुलना में, 2025-26 में 8.9 फीसद घट गयी और इसके तहत रोजगार पाने वालों की संख्या में 9.1 फीसद की कमी हो गयी। व्यक्ति-कार्यदिवसों की संख्या और भी तेजी से घटी है, पूरे 21.5 फीसद। इसका अर्थ यह है कि मनरेगा के अंतर्गत रोजगार पाने वाले मजदूरों को मुहैया कराए गए काम के दिनों की औसत संख्या में, उल्लेखनीय गिरावट हुई है। जहां तक समग्र परिमाण का सवाल है, जहां 2024-25 में मनरेगा के अंतर्गत 268.44 करोड़ व्यक्ति-दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया था, 2025-26 में 210.73 करोड़ व्यक्ति-दिवस का ही रोजगार उपलब्ध कराया गया। लिबटैक का अनुमान है कि अगर 2025-26 में प्रति परिवार औसत व्यक्ति-रोजगार दिनों की संख्या 2024-25 के बराबर ही रही हो, तो इसके तहत काम पाने वाले हरेक परिवार ने 2024-25 में, 2025-26 के मुकाबले 1938 रुपये यादा कमाए होंगे। दूसरे शब्दों में मनरेगा के कमजोर किए जाने के चलते, मजदूरों की इतनी आय मारी गयी है। किसी को यह लग सकता है कि हो सकता है कि 2024-25 का साल एक असामान्य साल हो और इसलिए उसके साथ तुलना से कोई भी नतीजा नहीं निकाला जा सकता हो। इसलिए, थोड़ा और पीछे जाना उचित होगा। बहरहाल, यह बात याद रखने की है कि महामारी के आने से ठीक पहले, 1919-20 के वर्ष में, मनरेगा के अंतर्गत 265.35 करोड़ व्यक्ति-दिनों का रोजगार सृजित किया गया था। दूसरे शब्दों में 2025-26 में आयी गिरावट, सिर्फ 2024-25 की तुलना में ही उल्लेखनीय नहीं है बल्कि महामारी से पहले के सामान्य समय की तुलना में भी उल्लेखनीय है।

कुछ लोगों ने 2025-26 में आयी इस गिरावट को, काम की मांग में आयी गिरावट से जोड़ने की कोशिश की है और काम की मांग में गिरावट को, भारतीय देहात में गरीबी के घटने का नतीजा बताने की कोशिश की है। लेकिन, यह पूरी तरह से बेतुकी दलील है। सिर्फ इतना ही नहीं कि ग्रामीण गरीबी में कमी इस तरह की दलील देने वालों की कल्पना की ही उपज है बल्कि यह तथ्य भी दर्ज करने वाला है कि 2025-26 में मनरेगा के लिए रोजगार हासिल करने के लिए नाम रजिस्टर कराने वाले परिवारों की संख्या भी वास्तव में 2024-25 के मुकाबले 3.2 फीसद बढ़ी ही थी और 2024-25 के 14.98 करोड़ से बढ़कर 15.46 हो गयी थी। जाहिर है कि अगर इस योजना के अंतर्गत रोजगार हासिल करने में लोगों की दिलचस्पी घट रही होती, तो वे बढ़ती संख्या में रोजगार के लिए अपने नाम दर्ज नहीं कर रहे होते।

ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम पर दोहरा हमला

मनरेगा के अंतर्गत रोजगार में गिरावट के कारणों में दो कारण खासतौर पर उभर कर सामने आते हैं। पहला है, मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन में 5 फीसद की कटौती किया जाना, जिसे अगर पिछले मजदूरी के बकाया 10,000 करोड़ से जोड़ दिया जाए, जिसका सबसे पहले भुगतान करना पड़ा होगा, यह इस योजना का वित्तीय पहलू से गला दबाए जाने का मामला हो जाता है। और इसका नतीजा, कम रोजगार दिए जाने के रूप में सामने आता है। संक्षेप में इस कार्यक्रम के लिए कम फंड मुहैया कराए जाने के जरिए, जान-बूझकर इसकी अधिकार-आधारित, मांग-संचालित प्रकृति का उन्मूलन किया जा रहा था। अगर योजना के लिए आवंटित फंड अपर्याप्त होने के चलते किसी वर्ष विशेष में मजदूरी समय पर नहीं दी जाती है या फंड का इस्तेमाल मजदूरी का पिछला बकाया चुकाने में होता है, तो संबंधित वर्ष के दौरान काम की मांग पूरी हुए बिना रह जाती है या मांग ही घट भी जाती है। उस सूरत में वित्त की उपलब्धता, एक व्यावहारिक अंकुश बन जाती है, जोकि वास्तव में यह बन गयी है। दूसरा कारण है, ''भ्रष्टाचार'' को रोकने के नाम पर, इस कार्यक्रम की प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकीय बदलाव किया जाना, जो व्यवहारत- बड़ी संख्या में मजदूरों का इस कार्यक्रम के दायरे से बहिष्करण बन जाता है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक विजय कुमार ने अशोक सम्राट प्रिन्टर्स, 215, पीरागढ़ी गांव, दिल्ली-87 से मुद्रित कर बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086 प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार। (RNI No. 70098/99) इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी हैं। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगें। Phone : 9810674206

तेल संकट के बीच सरकार का बड़ा कदम, पेट्रोल में 30फीसदी तक एथेनॉल मिश्रण की तैयारी

बिजनेस डेस्क। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल में अधिक एथेनॉल मिश्रण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पेट्रोल में 30त तक एथेनॉल मिश्रण (E30) के लिए नए नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने E22, E25, E27 और E30 ईंधन मिश्रण के लिए नए तकनीकी मानक जारी किए दिए हैं। इससे साफ संकेत मिला है कि सरकार भविष्य में पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल देशभर में श्व30 पेट्रोल की बिक्री शुरू नहीं की जा रही है। जारी नोटिफिकेशन केवल तकनीकी मानकों और गुणवत्ता संबंधी दिशा-निर्देशों से जुड़ा है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इन फ्यूल ब्लेंड्स को बाजार में उतारा जा सके। यानी यह कदम तत्काल लागू होने वाली व्यवस्था नहीं, बल्कि दीर्घकालिक तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच एथेनॉल ब्लेंडिंग को सरकार एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देख रही है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्षेत्र को लेकर चिंता बढ़ी है, जहां से दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति गुजरती है। ऐसे हालात में भारत जैसे तेल आयात पर निर्भर देशों के लिए वैकल्पिक ईंधन स्रोतों की अहमियत और बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने से न केवल कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी।

अक्षय कुमार के डांस की मुरीद हुईं अक्षरा सिंह, शेयर किया वीडियो; अभिनेता ने किया मजेदार रिप्लाई

अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के साथ भोजपुरी गाने पर डांस करने की ख्वाहिश जताई है। जिसका एक खास वीडियो अभिनेत्री ने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। अक्षरा सिंह ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो की शुरुआत में वह अपने टैब पर अक्षय कुमार का मशहूर गाना टिप-टिप बरसा पानी देखती नजर आ रही हैं। इसके बाद वह वीडियो में अक्षय कुमार से कहती हैं, प्रणाम अक्षय, मेरा नाम अक्षरा सिंह है और मैं भोजपुरी सिनेमा में काम करती हूं। अक्षरा ने आगे कहा, मैं काफी समय से आपके हिंदी गाने देख रही हूं। आपने कई हिंदी गानों पर डांस किया है, अब थोड़ा भोजपुरी गानों पर भी हमारे साथ ठुमका लगाइए। आप बस दिन और समय बता दीजिए, मैं आ जाऊंगी। अक्षरा ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, भोजपुरी गाने पर ठुमका लगाने का एक चांस दे दें क्या, अक्षय कुमार? अक्षरा सिंह का यह अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया क्रिएटर्स इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। अक्षरा के इस वीडियो पर अक्षय कुमार ने रिप्लाई दिया है। अक्षय ने लिखा, तो फिर बात पक्की अक्षरा। समय सुबह 11:30 बजे, दिन सोमवार, 25 मई और जगह सभी सोशल मीडिया। मिलते हैं।

खतरों के खिलाड़ी-15: रोहित शेट्टी की धमाकेदार एंट्री

रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 की शूटिंग केपटाउन में शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत होस्ट की धमाकेदार हेलीकॉप्टर एंट्री से हुई है। यह रोहित का 10वां सीजन है और इसमें नए-पुराने खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी, जो जुलाई में प्रसारित हो सकता है। रोहित शेट्टी एक बार फिर टीवी पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनका बेहद लोकप्रिय स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 जल्द ही दर्शकों के बीच आ रहा है। इस शो की शूटिंग के लिए सभी कंटेस्टेंट्स और खुद होस्ट रोहित शेट्टी साउथ अफ्रीका के खूबसूरत शहर केपटाउन पहुंच चुके हैं, जहां शो की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। रोहित शेट्टी ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके फैंस को इस बात की जानकारी दी है। हर बार की तरह इस बार भी रोहित शेट्टी ने शो में बेहद स्टाइलिश और एक्शन से भरपूर अंदाज में एंट्री की। वीडियो में वे हेलीकॉप्टर से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए रोहित शेट्टी ने भावुक कैप्शन भी लिखा,एक होस्ट के तौर पर यह मेरा 10वां सीजन है, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। आप सभी ने इतने सालों तक मुझे और मेरे शो को जो प्यार दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपसे वादा करता हूं कि यह सीजन और भी जबरदस्त होने वाला है। तो अपनी सीटबेल्ट्स बांध लें। खतरों के खिलाड़ी 15 जल्द ही आ रहा है। इस बार का सीजन बेहद रोमांचक होने वाला है क्योंकि शो में नए और पुराने खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। जहां कुछ नए चेहरे पहली बार खतरों का सामना करेंगे, वहीं कुछ पुराने खिलाड़ी अपने डर पर दोबारा जीत हासिल करने उतरेंगे। नए खिलाड़ियों में अविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट, ओरी, हर्ष गुजराल, शगुन शर्मा और रुहानिका धवन शामिल हैं। वहीं, रुबीना दिलैक, करण वाही, ऋत्विक धनजानी, अविका गोर, जैस्मिन भसीन और विशाल आदित्य सिंह जैसे पुराने खिलाड़ी भी शो का हिस्सा होंगे। खबरों के मुताबिक, खतरों के खिलाड़ी 15 की शुरुआत इस साल जुलाई के महीने में हो सकती है।

कंगना रनौत के Mangalsutra Look पर मचा बवाल, एक्ट्रेस ने Viral Photo पर तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी एक तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में हैं। दरअसल, हाल ही में उन्हें मुंबई में गले में मंगलसूत्र पहने स्पॉट किया गया था। इस लुक को देखने के बाद इंटरनेट पर यह अफवाहें उड़ने लगीं कि एक्ट्रेस ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। अब इन सभी चर्चाओं और अफवाहों पर खुद कंगना रनौत ने चुप्पी तोड़ी है और इसके पीछे का पूरा सच बताया है।

शादी की खबरों पर कंगना का जवाब

कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए साफ किया कि उन्होंने कोई शादी नहीं की है। उन्होंने बताया कि यह लुक उनकी आने वाली किसी फिल्म की शूटिंग का हिस्सा है। कंगना ने लिखा, मैं हर दिन शहर या आस-पास शूटिंग कर रही हूं। किसी ने मेरे कैरेक्टर मेकअप के साथ अचानक से मेरी एक तस्वीर खींच ली और अब मुझे इतने सारे फोन आ रहे हैं। लेकिन एक शादीशुदा महिला वाले लुक में इतनी बड़ी बात क्या है? एक्टर्स तो हर तरह के रोल निभाते हैं। मैं वादा करती हूं कि मैं गुपचुप शादी नहीं करूंगी।

भीषण गर्मी में शूटिंग पर क्या बोलीं कंगना?

शादी की अफवाहों के अलावा कंगना ने एक और पोस्ट शेयर करके इस समय पड़ रही भारी गर्मी और लू के बीच काम करने के अपने अनुभव को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि इस मौसम में शूटिंग करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। कंगना ने लिखा कि न्यूज एंकर अपने एसी स्टूडियो में बैठकर तापमान और लू की शिकायत करते हैं, लेकिन एक्टर्स और क्रू को भारी लाइट्स के बीच बंद जगहों पर बाहर शूटिंग करनी पड़ती है। हालांकि, उन्होंने सकारात्मक अंदाज में यह भी कहा कि शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी तब तक ही बेहतरीन है जब

जहां हुई थी रणबीर-आलिया की शादी, वही घर अब हुआ किराए पर; रेंट सुनकर उड़ जाएंगे होश; गौरी खान ने किया था डिजाइन

एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म रामायण फिल्म को लेकर चर्चाओं में हैं। ये एक मच-अवेटेड फिल्म है। फिल्म का पहला टीजर रिलीज होने के बाद से ही इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है। इस बीच एक्टर अपने लग्जरी मुंबई अपार्टमेंट को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर का पुराना घर, जो मुंबई के पॉश इलाके पाली हिल में स्थित है, अब नए किराएदार को मिल गया है। खास बात यह है कि इस घर का मंथली किराया सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणबीर कपूर ने अपना शानदार वास्तु अपार्टमेंट 11 लाख प्रति महीने के किराए पर लीज पर दिया है। यह अपार्टमेंट मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित पाली हिल इलाके में है। बताया जा रहा है कि यह डील 5 साल के लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत हुई है। करीब 2,460 स्क्वायर फीट में फैला यह लग्जरी अपार्टमेंट आदित्य शुक्ला को किराए पर दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, एग्रीमेंट में हर साल किराए में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी की शर्त भी शामिल है। वहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 45 लाख जमा किए गए हैं। खबरों की मानें तो रणबीर कपूर ने यह घर साल 2016 में लगभग 35 करोड़ में खरीदा था। इस घर के इंटीरियर्स को मशहूर डिजाइनर गौरी खान ने डिजाइन किया था, जो बॉलीवुड सितारों के आलीशान घरों को सजाने के लिए जानी जाती हैं। यह घर रणबीर कपूर के लिए काफी खास भी रहा है। इसी अपार्टमेंट में उन्होंने आलिया भट्ट के साथ

14 अप्रैल को बेहद निजी समारोह में शादी की थी। शादी घर की बालकनी में हुई थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं। करीब एक साल पहले रणबीर और आलिया अपनी बेटी राहा कपूर के साथ नए घर कृष्ण राज बंगला में शिफ्ट हो गए थे। पाली हिल में स्थित यह बंगला कपूर परिवार के लिए इमोशनल रूप से बेहद खास माना जाता है। बताया जाता है कि इसकी कीमत करीब 250 करोड़ है और यह रणबीर की मां नीतू कपूर के साथ मिलकर लिया गया है। वर्कफ्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर जल्द ही 'रामायण पार्ट 1' में नजर आएंगे, जिसे नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। यह फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज हो सकती है। इसके अलावा उनके पास 'लव एंड वॉर' और 'एनिमल पार्क' जैसी बड़ी फिल्में भी पाइपलाइन में हैं।

भजन-कीर्तन के साथ हुई करिश्मा तन्ना गोद भराई की रस्में

एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना और उनके पति वरुण बांगेरा के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली हैं। शादी के शानदार 4 साल पूरे करने के बाद यह कपल अब अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इसी बीच बीते दिन करिश्मा तन्ना की गोद भराई की रस्म बड़े ही धूमधाम से पूरी हुई। एक्ट्रेस ने इस बेहद खास और भावुक पल का एक खूबसूरत वीडियो खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फैंस के साथ शेयर किया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

पिंक साड़ी में दिखा करिश्मा का प्रेग्नेंसी ग्लो

अपनी गोद भराई के इस खास मौके पर करिश्मा तन्ना की खूबसूरती और उनका लुक सचमुच देखने लायक था। एक्ट्रेस ने इस खास पल के लिए एक बेहद प्यारी पिंक कलर की साड़ी चुनी थी, जिसमें उनका प्रेग्नेंसी ग्लो साफ नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ, उनके पति वरुण बांगेरा भी ट्रेडिशनल लुक में बेहद हैंडसम लग रहे थे। वरुण ने इस मौके पर सिंपल और क्लासिक व्हाइट कुर्ता-पजामा पहना हुआ था। पूरे फंक्शन के दौरान करिश्मा के चेहरे पर आने वाली मां की प्यारी मुस्कान छाई रही।

भजन-कीर्तन पर झूमा पूरा परिवार

इस खास दिन को और भी यादगार बनाने में करिश्मा और वरुण के परिवार और करीबी दोस्तों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गोद भराई की रस्मों के दौरान घर में भजन-कीर्तन का भी आयोजन किया गया था। इस माहौल में परिवार के सभी सदस्य खुशी से झूमते और नाचते हुए नजर आए। वहां मौजूद हर एक शख्स के चेहरे पर आने वाले नन्हे मेहमान को लेकर एक अलग ही खुशी और उत्साह साफ देखा जा सकता था।

अगस्त में गूंजेगी किलकारी, 2022 में हुई थी शादी

आपको बता दें कि करिश्मा तन्ना और वरुण बांगेरा ने इसी साल 6 अप्रैल को सोशल मीडिया पर कुछ बेहद क्यूट तस्वीरें शेयर करके अपने माता-पिता बनने की गुड न्यूज फैंस को दी थी। उन तस्वीरों में दोनों ने खास कैप पहनी हुई थी, जिस पर मॉम और डैड लिखा हुआ था। खबरों की मानें तो करिश्मा और वरुण के घर इस साल अगस्त महीने तक नन्हा मेहमान आ सकता है। याद दिला दें कि इस कपल ने 5 फरवरी 2022 को एक निजी समारोह में परिवार और खास दोस्तों की मौजूदगी में शादी रचाई थी।

जमीन कब्जाने और धन शोधन केस में ईडी का बड़ा एक्शन, कोलकाता से मुर्शिदाबाद तक कई ठिकानों पर छापेमारी

कोलकाता । प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार सुबह से कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर छापेमारी और तलाशी अभियान शुरू किया। यह कार्रवाई जमीन कब्जाने और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में की जा रही है, जिनमें कोलकाता पुलिस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर सिन्हा बिस्वास और कुख्यात स्थानीय भूमि माफिया बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू का नाम सामने आया है। सिन्हा बिस्वास और सोना पप्पू को इसी महीने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों एजेंसी की हिरासत में हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान मिले इनपुट और पूछताछ में सामने आए नामों के आधार पर शुक्रवार को कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक, ईडी की एक टीम शुक्रवार सुबह दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर इलाके के चक्रबेड़िया स्थित एक कारोबारी के घर पहुंची। अधिकारियों ने वहां पहुंचते ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया और दस्तावेजों व वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की। इसके कुछ ही देर बाद ईडी की दूसरी टीम सेंट्रल कोलकाता के रॉयड स्ट्रीट स्थित एक होटल पहुंची। जांच अधिकारियों ने सबसे पहले होटल मैनेजर से पूछताछ की और उसके बाद होटल परिसर में तलाशी अभियान शुरू किया। सूत्रों के अनुसार, होटल मालिक को भी तुरंत होटल पहुंचने के लिए कहा गया है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। इसी क्रम में ईडी की तीसरी टीम दक्षिण कोलकाता के कस्बा इलाके में एक पुलिस अधिकारी के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि यह पुलिस अधिकारी पूर्व डिप्टी कमिश्नर सिन्हा बिस्वास का करीबी सहयोगी माना जाता है। अधिकारियों ने वहां भी कई दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों की जांच की। सूत्रों का कहना है कि कारोबारी, होटल मालिक और पुलिस अधिकारी के नाम सिन्हा बिस्वास और सोना पप्पू से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जांच एजेंसी अब इन लोगों और जमीन सिंडिकेट के बीच संभावित आर्थिक लेनदेन तथा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़े सबूत जुटाने में लगी है। वहीं, ईडी की चौथी टीम मुर्शिदाबाद जिले के कांडी में स्थित सिन्हा बिस्वास के आलीशान पुश्तैनी मकान पर पहुंची। कांडी नगरपालिका के वार्ड नंबर आठ में स्थित इस मकान को लेकर भी जांच एजेंसी सक्रिय है। बताया जाता है कि इस मकान में पहले सिन्हा बिस्वास की बहन गौरी बिस्वास रहती थीं, जो तृणमूल कांग्रेस द्वारा संचालित कांडी नगरपालिका की वाइस चेयरमैन हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, सिन्हा बिस्वास की गिरफ्तारी के बाद से यह मकान बंद पड़ा था और उस पर ताला लगा हुआ था। शुक्रवार सुबह जब ईडी की टीम वहां पहुंची तो अधिकारियों को मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करना पड़ा। इसके बाद मकान के भीतर तलाशी अभियान शुरू किया गया, जो लंबे समय तक जारी रहा।

दालों के आयात में 34फीसदी की भारी गिरावट, घरेलू उत्पादन का असर

नई दिल्ली। देश में दालों के मजबूत घरेलू उत्पादन और कमजोर मांग के चलते वित्त वर्ष 2025-26 में दालों के आयात में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वाणिय विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में दालों का आयात मूल्य के आधार पर 34 प्रतिशत घटकर 3.63 अरब डॉलर रह गया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह रिकॉर्ड 5.54 अरब डॉलर था। मात्रा के लिहाज से भी दाल आयात 12 प्रतिशत घटकर 60 लाख टन रह गया, जो एक वर्ष पहले 73.4 लाख टन था। व्यापार सूत्रों के मुताबिक वैश्विक बाजार में दालों की कीमतों में भारी गिरावट और घरेलू स्तर पर पर्याप्त उत्पादन के कारण आयात में कमी आई है। हालांकि पश्चिम एशिया में जारी तनाव का अब तक दाल आयात पर बड़ा असर नहीं पड़ा है, लेकिन आने वाले समय में मानसून की स्थिति घरेलू उत्पादन और आयात की जरूरत तय करेगी। मौसम विभाग द्वारा सामान्य से कम बारिश की आशंका जताए जाने के कारण सरकार और कारोबारियों की नजर खरीफ उत्पादन पर बनी हुई है। वैश्विक बाजार में कीमतों में 30 से 40 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाली येलो पीज की कीमतें घटकर लगभग 300 डॉलर प्रति टन रह गई हैं, जबकि एक वर्ष पहले यह करीब 400 डॉलर प्रति टन थीं। इसी तरह चना दाल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें भी 650-670 डॉलर प्रति टन से घटकर 530 डॉलर प्रति टन पर आ गई हैं। इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के सचिव सतीश उपाध्याय ने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है, इसलिए फिलहाल आयात पर संकट का असर नहीं दिख रहा है। हालांकि भविष्य में आयात की मात्रा घरेलू उत्पादन की स्थिति पर निर्भर करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में येलो पीज और मसूर दाल के आयात में क्रमशः 47 प्रतिशत और 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं उड़द और अरहर के आयात में क्रमशः 25 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कुल आयात में अरहर की हिस्सेदारी सबसे अधिक 25 प्रतिशत रही, जबकि मसूर, येलो पीज और उड़द का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। देश अपनी कुल दाल खपत का लगभग 18 से 20 प्रतिशत हिस्सा कनाडा, रूस, ब्राजील, म्यांमार और अफ्रीकी देशों से आयात करता है। घरेलू आपूर्ति मजबूत रखने के लिए केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द के शुल्क-मुक्त आयात की अवधि मार्च 2027 तक बढ़ा दी है। वहीं येलो पीज पर 30 प्रतिशत और मसूर पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क जारी रहेगा। सरकारी एजेंसियों के पास मई की शुरुआत तक लगभग 26.9 लाख टन दालों का बफर स्टॉक मौजूद था। इसमें चना, अरहर, मसूर, मूंग और उड़द शामिल हैं।

भारतीय दवा उद्योग पर बड़ा संकट, बढ़ सकती हैं पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक्स की कीमतें

नई दिल्ली । ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता का बुरा असर अब आम इंसान की सेहत और जेब पर पड़ने वाला है। दुनिया भर में सबसे यादा सस्ती (जेनेरिक) दवाएं भेजने वाले भारत के दवा उद्योग पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। इस युद्ध के कारण दवा बनाने के लिए जरूरी कचे माल की कमी हो सकती है, माल ढुलाई का खर्च बढ़ सकता है और सप्लाई चेन टूट सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स और डायबिटीज जैसी आम बीमारियों की दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और इनकी कमी भी हो सकती है। ट्रंप मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनके नेतृत्व में अमेरिका का यह युद्ध वैश्विक व्यापार को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। फार्मेक्सिल (भारतीय औषधि निर्यात संवर्धन परिषद) और अन्य उद्योग संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव इसी तरह लंबे समय तक बना रहा, तो इसका बहुत भयंकर असर होगा। भारत लगभग 200 देशों को जेनेरिक दवाएं बेचता है। इस संकट का असर न केवल भारत पर पड़ेगा, बल्कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के उन तमाम गरीब देशों पर भी पड़ेगा, जो सस्ती दवाओं के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर हैं। वाणिय मंत्रालय के अनुसार, भारतीय दवा उद्योग का आकार लगभग 50 अरब डॉलर का है। दुनिया की कुल जेनेरिक दवा आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी करीब 20 प्रतिशत है। भारत भले ही दुनिया को सस्ती दवाएं बेचता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि दवा बनाने के लिए जरूरी कचा माल (एपीआई) इसे दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। साल 2025 में भारत ने लगभग 39,215 करोड़ रुपये के कचे माल का आयात किया था, जिसमें 70 से 75 प्रतिशत हिस्सा अकेले चीन का था। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध के कारण समुद्री मार्गों, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य और खाड़ी क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही रुकने से कचे माल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। कचा माल न पहुंचने का सबसे पहला और बड़ा असर उन दवाओं पर पड़ेगा जिनका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। सूत्रों के अनुसार, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज (मधुमेह) की दवाओं की सप्लाई पर सीधा संकट आ सकता है क्योंकि ये दवाएं मुख्य रूप से आयात किए गए कचे माल से ही बनती हैं। इसके अलावा, कैंसर की दवाओं और इंजेक्शन जैसी चीजों को तय तापमान में रखना होता है। लॉजिस्टिक्स उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि रास्ते बदलने और अतिरिक्त सुरक्षा के कारण माल ढुलाई का खर्च और समय दोनों बढ़ेंगे, जिससे दवाओं की लागत में भारी इजाफा होने की पूरी संभावना है।

शेयर बाजार में हरियाली; सेंसेक्स 315 अंक चढ़ा, निफ्टी 23700 के पार

नई दिल्ली । ईरान तनाव में नरमी की उम्मीद और वैश्विक आशावाद के चलते भारतीय बाजारों में शुक्रवार सुबह तेजी जारी रही। प्रमुख एशियाई सूचकांकों में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। भू-राजनीतिक तनाव में मिली संक्षिप्त राहत ने बाजार को सकारात्मक संकेत दिए। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 332.39 अंक चढ़कर 75,507.09 पर पहुंच गया; निफ्टी 84.60 अंक बढ़कर 23,747.40 पर पहुंच गया। बाजार विशेषज्ञों ने संस्थागत निवेश रुझानों और आगामी व्युत्पन्न अनुबंध समाप्ति के कारण सतर्क दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है। बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने सप्ताहांत में बिकवाली जारी रहने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक मई के अधिकांश समय में शुद्ध विक्रेता बने रहे। बग्गा ने अगले सप्ताह महीने के अंत की समाप्ति से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी। वैश्विक बाजार एक खतरनाक क्षेत्र में हैं, जहां एआई गति प्रमुख बाजारों को ऊपर ले जा रही है। ईरान युद्ध लगभग तीन महीने से जारी है, जिससे मुद्रास्फीति और ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो रही है। जापान की मुख्य मुद्रास्फीति उम्मीद से कम आने से एशियाई बाजारों को कुछ राहत मिली है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 2.61 फीसदी बढ़कर 63,293.00 पर पहुंच गया। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 1.34 फीसदी चढ़ा, जबकि ताइवान का भारित सूचकांक 1.28 फीसदी बढ़ा। राजनीतिक बयानों के बाद भू-राजनीतिक परिदृश्य में थोड़ा बदलाव आया है, जिससे तत्काल सैन्य वृद्धि में विराम का संकेत मिला। ट्रंप ने ईरान पर किसी भी कार्रवाई को टालने की इछा जताई, जिससे मध्यस्थता को मौका मिल सके। ब्रेंट क्रूड 1.54 फीसदी बढ़कर 104.16 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। कचा तेल भी 1.09 फीसदी बढ़कर 97.40 डॉलर पर पहुंच गया। अबू धाबी ने एक नई पाइपलाइन पर लगभग 50 फीसदी काम पूरा कर लिया है, जिससे 2027 तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर उसकी तेल निर्यात निर्भरता कम हो जाएगी। डॉलर के मुकाबले रुपया 0.06 फीसदी बढ़कर 96.23 पर रहा। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के शेयरों में शुक्रवार को करीब 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि कंपनी ने मार्च तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। बीएसई पर शेयर में 4.78 प्रतिशत की तेजी आई और यह 839 रुपये पर पहुंच गया। एनएसई पर शेयर 4.84 प्रतिशत बढ़कर 839 रुपये पर पहुंच गया। एलआईसी ने गुरुवार को मार्च तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 23,420 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो मुख्य व्यवसाय और निवेश पर प्रतिफल की बदौलत हुआ। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने पिछले साल की इसी तिमाही में 19,013 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था।

Wood Mackenzie की डरावनी चेतावनी, होर्मुज संकट से क्रूड 200 तक पहुंचने का खतरा

बिजनेस डेस्क । पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बनी अनिश्चितता ने वैश्विक ऊर्जा बाजार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ग्लोबल एनर्जी रिसर्च फर्म वुड मैकेंजी की ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि यह महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग लंबे समय तक बंद रहता है, तो दुनिया गंभीर ऊर्जा संकट और आर्थिक मंदी की ओर बढ़ सकती है। साथ ही कहा है क्रूड ऑयल का दाम 200 डॉलर प्रति बैरल के एतिहासिक स्तर पर पहुंच जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, होर्मुज स्ट्रेट से प्रतिदिन लगभग 1.1 करोड़ बैरल कचे तेल की आपूर्ति होती है, जो वैश्विक तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा यहां से सालाना 8 करोड़ टन से अधिक एलएनजी की आपूर्ति भी होती है, जो दुनिया के कुल एलएनजी व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत है। यदि यह आपूर्ति बाधित रहती है, तो वैश्विक ऊर्जा संतुलन गंभीर रूप से बिगड़ सकता है। डीजल और जेट फ्यूल की कीमतें 300 डॉलर प्रति बैरल के बराबर तक पहुंचने का खतरा भी जताया गया है, जिससे वैश्विक परिवहन और हवाई यात्रा पर भारी असर पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि संघर्ष साल के अंत तक जारी रहता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अफरातफरी फैल सकती है, क्योंकि किसी अन्य स्रोत से इतनी बड़ी आपूर्ति को तुरंत पूरा करना संभव नहीं है। इससे मालभाड़ा और सप्लाई चेन पर गंभीर दबाव बनेगा। हालांकि रिपोर्ट में तीन संभावित परिदृश्य भी बताए गए हैं। पहले परिदृश्य में यदि 2026 के मध्य तक शांति समझौता हो जाता है, तो बाजार धीरे-धीरे स्थिर हो सकता है और ब्रेंट क्रूड 2027 तक 65 डॉलर प्रति बैरल तक आ सकता है।

अशोका एक्सप्रेस
राष्ट्रीय हिन्दी समाचार-पत्र
प्रिय पाठक, विज्ञापन दाता,
आप अपने क्षेत्र की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य तथा धार्मिक लेख, कविता एवं कार्टून लिख भेजें। व्हाट्सएप या ईमेल पर आपके द्वारा भेजी गई सामग्री सुव्यवस्थित ढंग से प्रकाशित किया जायेगा।
नोट: पूर्व प्रकाशित लेखो को न भेजे।
संपादक: विजय कुमार
अशोका एक्सप्रेस को आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं।
Account Holder Name ASHOKA EXPRESS
Bank Account No.
IFSC Code
UPI ID

सप्ताह के दौरान सोना वायदा 2372 रुपये और चांदी वायदा

मुंबई। देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 15 से 21 मई के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 2660263.51 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 331916.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 2328344.66 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल साप्ताहिक प्रीमियम टर्नओवर 38654.45 करोड़ रुपये का हुआ। आलौय अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 211105.05 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 160790 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 160992 रुपये और नीचे में 157547 रुपये पर पहुंचकर, 161978 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2372 रुपये या 1.46 फीसदी लुढ़ककर 159606 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। गोल्ड-गिनी मई वायदा सप्ताह के अंत में 2105 रुपये या 1.62 फीसदी गिरकर 127780 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल मई वायदा 266 रुपये या 1.64 फीसदी लुढ़ककर सप्ताह के अंत में 15999 रुपये प्रति 1 ग्राम बंद हुआ। सोना-मिनी जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 160003 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 160349 रुपये और नीचे में 157152 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 2448 रुपये या 1.52 फीसदी औंधकर 159005 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम सप्ताह के आरंभ में 159962 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 160620 रुपये और नीचे में 157159 रुपये पर पहुंचकर, 161664 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2598 रुपये या 1.61 फीसदी गिरकर 159066 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा सप्ताह के आरंभ में 280000 रुपये के भाव पर खूलकर, 283219 रुपये के उच और 264949 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 291102 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 16219 रुपये या 5.57 फीसदी की गिरावट के साथ 274883 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा सप्ताह के अंत में 14893 रुपये या 5.07 फीसदी घटकर 278588 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 14889 रुपये या 5.07 फीसदी गिरकर सप्ताह के अंत में 278594 रुपये प्रति किलो हुआ। मेटल वर्ग में 36013.60 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए।

तांबा मई वायदा सप्ताह के अंत में 40.4 रुपये या 2.92 फीसदी औंधकर 1345.05 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता मई वायदा सप्ताह के अंत में 5 पैसे या 0.01 फीसदी के सुधार के साथ 367.45 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 1.25 रुपये या 0.32 फीसदी बढ़कर सप्ताह के अंत में 386.75 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि सीसा मई वायदा सप्ताह के अंत में 40 पैसे या 0.2 फीसदी की नरमी के साथ 203.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 84786.45 करोड़ रुपये के सौदे किए।

एमसीएक्स क्रूड ऑयल जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 9458 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 10150 रुपये के उच और 9211 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 8 रुपये या 0.09 फीसदी लुढ़ककर 9342 रुपये प्रति बैरल बंद हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जून वायदा सप्ताह के अंत में 9 रुपये या 0.1 फीसदी गिरकर 9339 रुपये प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा सप्ताह के आरंभ में 281 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 303.4 रुपये के उच और 277.7 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 277.4 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 12.7 रुपये या 4.58 फीसदी की मजबूती के साथ 290.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा सप्ताह के अंत में 12.7 रुपये या 4.58 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 290.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा सप्ताह के आरंभ में 994.5 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 9.2 रुपये या 0.93 फीसदी गिरकर 985.3 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर आलौय अवधि के सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 101427.67 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 109677.38 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 27598.50 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 4239.52 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 103.27 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 3951.14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 54086.50 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 30600.96 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 10.81 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 5799 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 35596 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 6309 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 82823 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 17242 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9189 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19929 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 48953 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 14227 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 12420 लोट के स्तर पर था।

पकड़ी नोनिया में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर जागरूकता गोष्ठी आयोजित

महराजगंज।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर पकड़ी रेंज अंतर्गत पकड़ी नोनिया गाँव में एक प्रभावी जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को जैव विविधता के महत्व से अवगत कराना तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति उनकी जिम्मेदारी को सुदृढ़ करना था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता देखने को मिली, जिससे कार्यक्रम सफल और सार्थक रहा।क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री सुशांत मणि त्रिपाठी ने कहा कि जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि जैव विविधता केवल वन्य जीवों और पेड़-पौधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है, जो मानव जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव-

जंतुओं के संरक्षण की आवश्यकता पर विशेष जोर देते हुए सतत विकास के उपायों पर भी चर्चा की गई।उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सरल और व्यावहारिक उपायों के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। जैसे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जीवनशैली अपनाना। ग्रामीणों को यह भी बताया गया कि छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं।क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री सुशांत मणि त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि जैव विविधता पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की रीढ़ है। इसके बिना न तो प्रकृति सुरक्षित रह सकती है और न ही मानव जीवन। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैव विविधता का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि यहां की अर्थव्यवस्था और जीवनशैली सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने आसपास की प्राकृतिक संपदा की रक्षा करें और बच्चों को भी इसके संरक्षण के प्रति जागरूक बनाएं।इस दौरान वन दरोगा विपुल कुमार मिश्रा, वन रक्षक विक्रांत सिंह, वन्यजीव रक्षक शशि चौधरी सहित अन्य वनकर्मी तथा वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही ग्राम प्रधान इन्द्रमणि वर्मा मौजूद रहे।

मंच पर जुटी जनप्रतिधियों की फौज, सांसद शशांक मणि और कृषि मंत्री शाही ने किया सीएम का स्वागत

देवरिया। भीमपुर गौरा का यह भव्य मंच राजनीतिक एकजुटता और जनपद के विकास के साझा संकल्प का गवाह बना। जनसभा की शुरुआत में सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह और स्थानीय प्रतीक भेंट कर उनका स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह, ग्राम्य विकास रायमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, और सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा रखा। वक्ताओं ने कहा कि आज देवरिया को जो फोरलेन की कनेक्टिविटी मिल रही है, वह यहां के आर्थिक भूगोल को बदल देगी। इस दौरान बरहज विधायक दीपक मिश्रा, भाटपाररानी विधायक सभाकुंवर, रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद और रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने भी अपने-अपने क्षेत्रों की जन-आकांक्षाओं को मंच के माध्यम से साझा किया। कार्यक्रम में एडीएम, सीएमओ और दोनों नगर पालिकाओं की अध्यक्षों सहित भारी संख्या में जनसामान्य की उपस्थिति रही, जिसने इस आयोजन को एक जन-उत्सव में बदल दिया।

प्रशासनिक स्टॉल्स पर पहुंचे सूबे के मुखिया, खुद कराई बच्चों की गोदभराई और अन्नप्राशन

देवरिया। जनसभा से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल पर कलेक्ट्रेट प्रशासन और विभिन्न विकास विभागों द्वारा लगाए गए 15 विशेष स्टॉल्स का बेहद आत्मीयता से निरीक्षण किया। बाल विकास परियोजना (आईसीडीएस) के स्टॉल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने खुद नवजातों का अन्नप्राशन कराया और गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की रस्म पूरी कर उन्हें पोषण किट प्रदान की। दिव्यांगजन कल्याण विभाग के स्टॉल पर उन्होंने दिव्यांग नागरिकों से सीधे संवाद कर उन्हें आधुनिक ट्राइसाइकिल वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र गोरखपुर व बस्ती, गन्ना विभाग, उद्यान, राय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदर्शित किए गए स्थानीय उत्पादों और मॉडलों की गहन समीक्षा की।

एसी से अचानक गर्मी में जाना खतरनाक, हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक; डॉक्टर ने बताया बचाव का तरीका

गोरखपुर। भीषण गर्मी के बीच राहत पाने के लिए लोग लगातार एयर कंडीशनर (एसी) का सहारा ले रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे लेकर गंभीर चेतावनी दी है। डाक्टरों का कहना है कि एसी से अचानक तेज गर्मी में निकलना या बाहर की गर्मी से सीधे वातानुकूलित कमरे में पहुंचना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। तापमान में अचानक होने वाला यह बदलाव शरीर और मस्तिष्क पर प्रतिकूल असर डालता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बीआरडी मेडिकल कालेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में न्यूरो सर्जरी व न्यूरोलाजी ओपीडी में इन दिनों ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

अस्पताल में प्रतिदिन 25 से 30 ब्रेन स्ट्रोक पीड़ित पहुंच रहे हैं। डाक्टरों का कहना है कि इनमें से अधिकांश मामलों में अचानक ठंडे और गर्म वातावरण के बीच बार-बार आने-जाने की आदत प्रमुख कारण बनकर सामने आई है। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन भी इस समस्या को बढ़ा रहा है। यदि समय-समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिया जाए तो निर्जलीकरण की समस्या बढ़ जाती है। डिहाइड्रेशन के कारण खून गाढ़ा होने लगता है, जिससे मस्तिष्क तक रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकता है और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। बुजुर्गों, उच रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक एसी में रहने के बाद अचानक तेज धूप या गर्म वातावरण में जाता है तो शरीर को तापमान के अनुरूप ढलने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इससे रक्तचाप में तेजी से उतार-चढ़ाव होता है और मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ जाता है। यही स्थिति ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकती है। इसी तरह तेज गर्मी से सीधे अत्यधिक ठंडे कमरे में पहुंचने पर भी शरीर पर अचानक दबाव पड़ता है, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। गर्मी के मौसम में शरीर से अत्यधिक पसीना निकलने के कारण पानी और आवश्यक लवणों की कमी हो जाती है।

स्वास्थ्य विभाग में 24 आउटसोर्स कर्मियों की सेवा समाप्त, नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला

कुशीनगर। स्वास्थ्य विभाग में नियमों को दरकिनार कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किए गए 24 सफाईकर्मी एवं सपोर्ट स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) की ओर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में नियुक्तियों में अनियमितता पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार करीब तीन माह पूर्व तत्कालीन सीएमओ डॉ सुरेश पटारिया के कार्यकाल में 12 अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को लेकर शिकायत सामने आई थी। मामले की जांच में नियुक्तियां नियमविरुद्ध पाए जाने पर जिलाधिकारी के आदेश से उन्हें निरस्त कर दिया गया। इसके बाद अन्य नियुक्तियों की भी समीक्षा की गई, जिसमें कुल 24 कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। मामले में तत्कालीन कार्यवाहक सीएमओ डॉ बृजनंदन के कार्यकाल पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब तक संबंधित अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले को लेकर लोगों में चर्चा है कि यदि आम व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की फर्जीवाड़े की घटना की जाती तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई होती। ऐसे में अब निगाहें शासन और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

धोनी की वापसी पर सस्पेंस जारी; सीएसके के कोच ने माही के भविष्य पर दिया बड़ा अपडेट, कहा- जब सही लगेगा...

चेन्नई । चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2026 अभियान गुजरात टाइटंस से 89 रन की हार के साथ खत्म हो गया। टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई, लेकिन मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा एमएस धोनी के भविष्य को लेकर हुई। पूरे सीजन धोनी मैदान से दूर रहे। उन्होंने एक भी मुकाबला नहीं खेला और यादातर अवे मैचों में टीम के साथ यात्रा भी नहीं की। ऐसे में फैंस लगातार यह जानना चाहते थे कि क्या यह उनका आखिरी आईपीएल सीजन था। सीएसके के बॉलिंग कोच एरिक सिमंस ने धोनी की फिटनेस और मानसिकता पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, क्या आप सच में मुझसे यह सवाल पूछ रहे हैं? सिमंस ने आगे कहा, ईमानदारी से कहूं तो वह गेंद को शानदार तरीके से हिट कर रहे थे। लेकिन पैर की चोट की वजह से उनके लिए दौड़ना मुश्किल हो गया था। इसी कारण वह नहीं खेल सके। नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए मैंने उन्हें पहले जितना ही शानदार देखा। धोनी पहले से पैर की चोट से जूझ रहे थे। इसके बाद अंगूठे में नई चोट लगने से उनकी वापसी की उम्मीद भी खत्म हो गई। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी मुकाबले में भी वह टीम के साथ मौजूद नहीं थे और इलाज के लिए रांची लौट गए थे। चेपॉक में फैंस को धन्यवाद देने के दौरान भी उनका अंगूठा भारी टेप से बंधा नजर आया था। सिमंस ने साफ किया कि धोनी के भविष्य का फैसला वही खुद करेंगे। उन्होंने कहा, धोनी खुद जानेंगे कि वह कब तैयार हैं। अगर उन्हें लगेगा कि यह सही नहीं है तो वह नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि वह तैयार हैं तो जरूर खेलेंगे। वह हमेशा टीम के हित में फैसला लेते हैं। वहीं सुरेश रैना ने भी हाल ही में धोनी से मुलाकात की थी। चेन्नई के आखिरी घरेलू मैच के बाद रैना ने धोनी के साथ लैप ऑफ ऑनर लिया था। इसके बाद उन्होंने खुलासा किया कि जब उन्होंने धोनी से अगले सीजन खेलने को लेकर पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा- देखते हैं। हालांकि, धोनी के यही तीन शब्द अब सीएसके फैंस के लिए नई उम्मीद बन गए हैं।

विराट कोहली के साथ बैटिंग से आया बहुत बड़ा फर्क, देवदत्त पडिक्कल ने खोला अपनी सफलता का राज

आरसीबी के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने अपने आईपीएल करियर पर विराट कोहली के गहरे प्रभाव का विश्लेषण किया है, बताते हुए कि कैसे कोहली के साथ बल्लेबाजी करने से उनकी पारी को समझने और उसे सही ढंग से आगे बढ़ाने की क्षमता में बहुत बड़ा फर्क पड़ा। मौजूदा आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टूर्नामेंट के इस संस्करण में शानदार फॉर्म में है। टूर्नामेंट में प्रवेश करते हुए, आरसीबी नॉकआउट चरणों से पहले अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। ग्रुप चरण के अपने अंतिम मैच के लिए तैयार टीम के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने मंच पर आकर अनुभवी भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के साथ खेलने के अनुभव और इससे उनके करियर को आकार देने में मिली मदद के बारे में बात की। देवदत्त पडिक्कल ने जियोहॉटस्टार को बताया कि जब मैंने 2020 सीज़न में आरसीबी के साथ आईपीएल में पदार्पण किया, तो मैं पूरी तरह तैयार था। घरेलू क्रिकेट में मेरा प्रदर्शन शानदार रहा था। इसलिए, मुझे पता था कि जब मुझे मौका मिलेगा, तो मैं पूरी तरह से तैयार रहूंगा और अपना 100 प्रतिशत दूंगा। और खेल के महानतम खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी करना मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुआ। उस उम्र में, उन्हें पारी की रचना करते हुए देखकर मुझे पारी को सही ढंग से खेलने का तरीका बहुत अच्छे से समझ आया। इससे मेरे विकास में बहुत बड़ा फर्क पड़ा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के शेड्यूल की बात करें तो, मौजूदा चैंपियन टीम का अगला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। टूर्नामेंट का 67वां मैच 22 मई को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों का यह आखिरी मैच होगा। हालांकि दोनों टीमें नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के पास अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने का मौका है और इसके लिए उन्हें मौजूदा चैंपियन टीम पर बड़ी जीत दर्ज करनी होगी।

ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने को तैयार पाकिस्तान टीम बाबर आजम और नसीम शाह समेत दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जो 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी।

पीसीबी की वेबसाइट के अनुसार, तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया है, जबकि सलमान अली आगा उप-कप्तान होंगे। इस टीम में बाबर आजम, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान और सुफयान मोकिम जैसे प्रमुख खिलाड़ियों की वापसी भी हुई है, जो मार्च में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैचों की टीम में अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास और रोहैल नज़ीर तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं। सलमान अली आगा, अब्दुल समद, अबरार अहमद, माज़ सदाकत, मोहम्मद ग़ाज़ी घोरी, साहिबज़ादा फरहान और शमिल हुसैन ने बांग्लादेश सीरीज में खेलने के बाद अपनी टीम में जगह बरकरार रखी है। मोहम्मद ग़ाज़ी घोरी और रोहैल नज़ीर को विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में नामित किया गया है, जबकि उस्मान खान बीमारी के कारण टीम से बाहर हैं। 16 सदस्यीय टीम आज इस्लामाबाद में एकत्रित होगी और शनिवार से कोचिंग स्टाफ के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण शुरू करेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम शनिवार को इस्लामाबाद पहुंचेगी। वे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेंगे।

फखर जमान और साइम अयूब अभी भी चोट से उबर रहे हैं और उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करते हुए तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली थी और मेहमान टीम को 3-0 से हराया था।

ऑस्ट्रेलिया वनडे के लिए पाकिस्तान टीम

शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), सलमान अली आगा, अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास, बाबर आजम, हारिस रऊफ, माज सदाकत, गाजी गोरी, नसीम शाह, रोहेल नजीर, साहिबजादा फरहान, शादाब खान, शमील हुसैन और सुफयान मोकिम।

रुतुराज गायकवाड को महंगी पड़ी कप्तानी, धीमी ओवर-रेट के लिए लगा 24 लाख का जुर्माना

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि टीम ने 31 जनवरी, 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स (जीटी) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के मैच के दौरान दूसरी बार धीमी ओवर-रेट का उल्लंघन किया था। इस उल्लंघन के लिए सीएसके के बाकी ग्यारह खिलाड़ियों और इम्पैक्ट प्लेयर्स पर भी जुर्माना लगाया गया है। आईपीएल के एक बयान में पुष्टि की गई है कि गायकवाड़ को आईपीएल आचार संहिता के अनुछेद 2.22 के तहत दंडित किया गया है, जो न्यूनतम ओवर-रेट उल्लंघन से संबंधित है। बयान में कहा गया है, चूंकि यह उनकी टीम का इस सीज़न का दूसरा उल्लंघन था (पहला उल्लंघन मैच 18 में हुआ था), इसलिए गायकवाड़ पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्लेइंग इलेवन के बाकी सदस्यों, जिनमें इम्पैक्ट प्लेयर भी शामिल है, पर या तो 6 लाख रुपये या उनकी संबंधित मैच फीस का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, का जुर्माना लगाया जाएगा। इस मैच में गुजरात टाइटन्स ने सीएसके पर 89 रनों की शानदार जीत दर्ज की, जिसमें सभी खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन का अहम योगदान रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए जीटी ने 229 रन बनाए, जिसमें शुभमन गिल (64), साई सुदर्शन (84) और जोस बटलर (57 नाबाद) का अहम योगदान रहा। तेज सलामी साझेदारी और स्थिर स्कोरिंग के बाद जीटी ने यह उपलब्धि हासिल की। जवाब में सीएसके 140 रनों पर ऑल आउट हो गई। मोहम्मद सिराज ने तीन विकेट लेकर शुरुआती विकेटों से ही मैच की दिशा तय कर दी, वहीं कगिसो रबाडा और राशिद खान ने भी तीन-तीन विकेट लिए। शिवम दुबे के 47 रनों की तेज पारी के बावजूद सीएसके की पारी लड़खड़ा गई और वे 20 ओवर के अंदर ही ऑल आउट हो गए। इस हार के साथ ही सीएसके का आईपीएल 2026 का सफर समाप्त हो गया, क्योंकि टीम लगातार तीसरे सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने में असफल रही।

विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, अयोग्य घोषित करने के फैसले पर कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को फटकारा

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को फटकार लगाई। डब्ल्यूएफआई ने पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि विशेषज्ञों की टीम बनाकर विनेश की स्थिति का मूल्यांकन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वह ट्रायल में हिस्सा ले सकें। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने केंद्र सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि फोगाट को आने वाले एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। विनेश मातृत्व अवकाश के बाद खेल में वापसी करना चाहती हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि डब्ल्यूएफआई का शीर्ष खिलाड़ियों को भाग लेने की अनुमति देने की पूर्व प्रथा पर नहीं चलना 'बहुत कुछ कहता है'। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि देश में मातृत्व का जश्न मनाया जाता है और संघ को 'प्रतिशोध' की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए। अदालत ने केंद्र से फोगाट का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने को कहा। हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, विशेषज्ञों से उसकी संभावनाओं का मूल्यांकन करने को कहें। यह सुनिश्चित करें कि वह भाग ले सके। बता दें कि इससे पहले 18 मई को हाई कोर्ट ने विनेश फोगाट को 30 और 31 मई को होने वाले एशियन गेम्स चयन ट्रायल में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। वहीं, डब्ल्यूएफआई ने हाल ही में विनेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और जून 2026 तक घरेलू टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया था। विनेश ने इस नोटिस को चुनौती दी थी जिस पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई।

क्यों भेजा था कारण बताओ नोटिस

डब्ल्यूएफआई ने हाल ही में अनुशासनहीनता और डोपिंग विरोधी नियमों के उल्लंघन के आरोपों पर विनेश को नोटिस भेजा था।

इतना ही नहीं विनेश जून 2026 तक घरेलू टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित की गईं क्योंकि उन्होंने यूडब्ल्यूडब्ल्यू के डोपिंग रोधी नियम के तहत संन्यास से वापसी के बाद जरूरी छह महीने का नोटिस पीरियड नहीं दिया है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया था कि यदि विनेश दोबारा कुश्ती में वापसी करना चाहती हैं, तो उन्हें आईटीए या इंटरनेशनल फेडरेशन को कम से कम छह महीने पहले सूचना देनी होगी और इस दौरान एंटी-डोपिंग टेस्टिंग के लिए उपलब्ध रहना होगा। 15 पन्नों के नोटिस में, डब्ल्यूएफआई ने आरोप लगाया था कि विनेश के आचरण ने राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा किया है जिससे भारतीय कुश्ती की छवि को नुकसान पहुंचा है। डब्ल्यूएफआई ने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि विनेश इस वर्ष 26 जून तक किसी भी घरेलू प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं, जिसमें गोंडा में 10 से 12 मई तक होने वाला राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट भी शामिल था।

नीट अब नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुका है, जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर किया तीखा हमला

नई दिल्ली। कांग्रेस ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक अभिषेक सिंह द्वारा संसद की एक समिति के समक्ष की गई टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में हुई धांधली को दबाने का प्रयास हो रहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि देश के लाखों युवाओं के लिए एनटीए अब नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुका है। एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी बृहस्पतिवार को संसद की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति के सामने पेश हुए थे। सूत्रों के अनुसार, जब समिति के कई सदस्यों ने सवाल किया कि नीट-यूजी परीक्षा का पेपर कैसे लीक हुआ, तो एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने उन्हें बताया कि परीक्षा का कोई पेपर उनके सिस्टम के माध्यम से लीक नहीं हुआ। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, 2018 में एनटीए के गठन के बाद से मोदी सरकार और उसका तंत्र एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और धोखाधड़ी की सचाई को दबाने के लिए पेपर लीक माफिया के साथ मिलीभगत कर रहा है।

आज हमें खबरों से पता चला है कि एनटीए महानिदेशक ने कल एक संसदीय समिति के सामने दावा किया था कि नीट-यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ था। रमेश के अनुसार, यदि यह सच है, तो यह बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली बेईमानी है क्योंकि यह स्पष्ट है कि एक गेस पेपर, जिसमें असल परीक्षा में आए दर्जनों सवाल शामिल थे, परीक्षा की तारीख से काफी पहले छात्रों के पास था। रमेश ने सवाल किया, अगर यह लीक नहीं है, तो फिर क्या है? मोदी सरकार अब इसे नकारने की कोशिश क्यों कर रही है? उन्होंने कहा, मोदी सरकार इससे पहले भी नीट-यूजी 2024 में सामने आई व्यापक अनियमितताओं को दबाने की कोशिश कर चुकी है। यदि उस समय सचाई स्वीकार कर कार्रवाई की गई होती, तो शायद नीट 2026 की यह त्रासदी टाली जा सकती थी। उनके मुताबिक, धोखाधड़ी से कथित तौर पर संबद्ध जिन केंद्रों की खबरें 2024 में सामने आई थीं, वे ही 2026 के इस घोटाले में भी सामने आए हैं, जैसे कि राजस्थान का सीकर है। रमेश ने कहा, परेशान करने वाली घटनाओं की कड़ी में सीबीआई ने 2024 की यूजीसी नेट परीक्षा में किसी भी अनियमितता से इनकार करते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, जबकि उस परीक्षा को उसी समय एनटीए द्वारा रद्द किया गया था। जब दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई से उसकी क्लोजर रिपोर्ट पर लिखित स्पष्टीकरण मांगा, तो सीबीआई ने और समय मांग लिया। उनका कहना है, अदालत ने भले ही इस देरी पर सीबीआई को फटकार लगाई हो, लेकिन उसके रवैये से नीट जांच में न्याय सुनिश्चित करने की उसकी मंशा पर कोई भरोसा नहीं पैदा होता। कांग्रेस नेता ने दावा किया, देश के लाखों युवाओं के लिए एनटीए अब नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुका है। सीबीएसई, एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय के अन्य संस्थान, जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, कोई बेहतर स्थिति में नहीं हैं। शिक्षा मंत्री ऐसे तंत्र की अगुवाई कर रहे हैं, जहां पेशेवर उत्कृष्टता की कोई कद्र नहीं है और वैचारिक नजदीकी को सबसे यादा महत्व दिया जाता है। रमेश ने कहा, इस भयानक त्रासदी और उसे लगातार दबाने की कोशिशों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दोनों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

एनसीईआरटी किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला चैप्टर लिखने वाले राइटर्स को बड़ी राहत, नहीं जाएगी नौकरी

नई दिल्ली। एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला चैप्टर लिखने के लिए जिम्मेदार तीन राइटर्स को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों लेखकों मिशेल डैनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार पर सरकारी नौकरियों से रोक लगाने वाला आदेश वापस लिया है. इससे पहले कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आदेश जारी किया था कि इन सभी को तुरंत सभी सरकारी कामकाज से हटाया जाए. हालांकि अब इन सभी को राहत दे दी गई है. ह्यष्टश्वत्रक्ष की कक्षा 8वीं किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का एक चैप्टर जोड़ा गया था. इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे कोर्ट भी भ्रष्टाचार से अछूते नहीं हैं. इसके लिए पूर्व सीजेआई के एक बयान का भी जिक्र किया गया था. मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस चैप्टर को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन्हें तुरंत सभी रायों, केंद्र शासित प्रदेशों और विश्वविद्यालयों में सरकार के वित्तपोषित सिलेबस और शैक्षणिक परियोजनाओं से अलग कर दिया जाए. इन लोगों को किसी भी सरकारी कामकाज में शामिल नहीं किया जाएगा. इस आदेश के बाद से ही तीनों राइटर्स की नौकरी पर संकट मंडरा रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने नरमी दिखाते हुए अपना आदेश वापल ले लिया है. स्कूल की किताब में इस तरह के चैप्टर को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने न्यायपालिका की गरिमा पर प्रहार बताया था. इसके बाद इस किताब की तमाम सॉफ्ट कॉपियों को भी हटाया गया और फिर से नया चैप्टर लिखने का आदेश जारी हुआ. वहीं ह्यष्टश्वत्रक्ष की तरफ से बताया गया कि इस चैप्टर का उद्देश्य संवैधानिक समझ और संस्थागत सम्मान बढ़ाना था. इस चैप्टर में अदालतों में लंबित पड़े हजारों मामलों का जिक्र भी किया गया था.

दिल्ली में पानी-सीवर कनेक्शन सस्ता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐलान, डीजेबी शुल्कों में भारी कटौती

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के बुनियादी ढांचा शुल्कों में बड़े पैमाने पर युक्तिकरण की घोषणा की। यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस निर्णय की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ...हमने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लगाए जा रहे बुनियादी ढांचा शुल्कों को पूरी तरह से युक्तिकरण करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब, पानी और सीवर के लिए बुनियादी ढांचा शुल्क केवल पानी की आवश्यकता के आधार पर लगाया जाएगा... शुल्क पानी की आवश्यकता के अनुसार होगा। बुनियादी ढांचा शुल्क केवल नए निर्माण या अतिरिक्त निर्माण पर ही लगाया जाएगा... खुले क्षेत्रों में पानी की आवश्यकता को बुनियादी ढांचा शुल्क में शामिल नहीं किया जाएगा। बाद में दिन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी में आधुनिक मुखमेलपुर पार्क की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण लगभग 1 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर कहा कि लगभग 3 एकड़ में विकसित किए जा रहे इस पार्क में पैदल मार्ग, झोपड़ियां, एक तालाब और आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएं होंगी। इस बीच, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को घोषणा की कि नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया 15 मई से बड़े पैमाने पर फिर से शुरू हो गई है, जिससे लगभग 13 वर्षों का इंतजार समाप्त हो गया है।

उन्होंने कहा कि पात्र और जरूरतमंद परिवारों से आवेदन करने का आग्रह किया और कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय विजन को लागू कर रही है ताकि कल्याणकारी लाभ उन लोगों तक पहुंचें जिन्हें वास्तव में इनकी सबसे यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए राशन कार्ड और परिवार के सदस्यों को जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई से ई-जिला पोर्टल के माध्यम से शुरू हो गए हैं। अतीत में जमा किए गए पुराने आवेदन भी आवेदकों को उनके लॉगिन प्रोफाइल के माध्यम से वापस कर दिए गए हैं। आवेदक वैध पारिवारिक आय प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ उन्हें अपडेट और पुनः जमा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली का व्यापक ऑडिट किया, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर हुईं। कुल 7,71,384 अपात्र फर्जी लाभार्थियों की पहचान की गई। इनमें से 6,46,123 लाभार्थी निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले पाए गए और इसलिए सब्सिडी वाले राशन के लिए अपात्र थे।

अन्य 95,682 लाभार्थियों ने एक वर्ष से अधिक समय से राशन का लाभ नहीं उठाया था। गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 6,185 मामलों में मृत व्यक्तियों के नाम राशन रिकॉर्ड में दर्ज थे, जबकि 23,394 लाभार्थी कई स्थानों से लाभ प्राप्त कर रहे थे।

भारत-साइप्रस के बीच द्विपक्षीय वार्ता, पीएम मोदी बोले- समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंध

नई दिल्ली।

भारत और साइप्रस के संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस के बीच नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती न केवल मजबूत है, बल्कि भविष्य की जरूरतों और संभावनाओं के अनुरूप भी है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री समेत दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

दोनों देशों के संबंध के बारे में पीएम ने क्या कहा?

पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध समय की कसौटी पर बार-बार खरे उतरे हैं और अब इन्हें नई दिशा देने के लिए रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करते हुए कहा कि पिछले वर्ष साइप्रस यात्रा के दौरान उन्हें मिले गर्मजोशी भरे स्वागत और सम्मान को भारत कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि साइप्रस द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के प्रति सम्मान और दोनों देशों के गहरे रिश्तों का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस की साझेदारी

लोकतंत्र, कानून के शासन और संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत हमेशा इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगा।

भारत और साइप्रस के बीच निवेश का लक्ष्य

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हुआ है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के चलते कई नई आर्थिक संभावनाएं खुली हैं और भारत अगले पांच वर्षों में इस निवेश को फिर से दोगुना करने का लक्ष्य रखता है।

वैश्विक मुद्दों पर भी हुई चर्चा

उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के बीच वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चाहे यूक्रेन का मुद्दा हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, भारत शांति और संघर्षों के जल्द समाधान के प्रयासों का समर्थन करता रहेगा।

साथ ही उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार को जरूरी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत-साइप्रस रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा, नई महत्वाकांक्षा और नई गति लेकर आएगी।

राष्ट्रपति निकोस ने बताया यात्रा का मुख्य फोकस

साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस ने कहा कि उनका मुख्य फोकस भारत और साइप्रस के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलिडेस ने कहा कि मैं आज यहां केवल साइप्रस गणराय के राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि यूरोपीय संघ के उस सदस्य देश के प्रतिनिधि के रूप में भी मौजूद हूं, जो वर्तमान में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाल रहा है।

माननीय प्रधानमंत्री-भारत सरकार, श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री, श्रीमती रेखा गुप्ता जी

पूर्व केजरीवाल सरकार का कमाऊ पूत

सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के

ई.ई, ए.ई, कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा 11 वर्षो से विकास एवं निर्माण कार्य में बेहद घटिया निर्माण सामग्री व फर्जी बिल लगाकर।

करोड़ो के घोटाले व भष्टाचार की जांच

श्रीमान निदेशक, सीबीआई, भारत सरकार से कराई जाएं।

छठ घाटो में टेन्ट, पानी टैंकर, बड़े नालो की साफ-सफाई, बॉउन्ड्रीवाल के फर्जी बिल लगाकरकिए गए करोड़ो के घोटाले और हरे-भरे पेड़ो को काटकर खुलेआम बेचा जा रहा है।

I&FC के श्री अशोक कुमार-(FC-III), ए.सुरेन कुमार (पीएनडी), अनुराग जैन (CD-I), विवेक चौहान (CD-II), शोभित जैन (CD-III), सोमनाथ कश्यप (CD-IV), बी.बी.नागपाल (CD-V), जे.नरेन्द्र सागर (CD-VI) प्रदीप नैक (CD-VII), पुनित डुडेजा (CD-IX), प्रशांत मिश्रा (CD-X), विवेक चौहान (CD-XI), गगन गौड़ (CD-XII), सुधीर कुमार आर्य (S.W-1 & CD-XIII), शिव कुमार (CD-XIV), जे.नरेन्द्र सागर (CD-XV) एई, जे.ई ने ठेकेदारों की मिलीभगत से दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों के विकास एवं निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री और फर्जी बिल बनाकर कर रहे है अपना समाजवाद दूर!

भ्रष्टाचारियों व कमिशन खोरो का अड्डा बना श्री सुधीर कुमार आर्य, ई.ई, सतर्कता कार्यालय: बसई दारापुर?

निवेदक: अपराध एवं भ्रष्टाचार निरोधक मोर्चा (विज्ञापन)